पूर्व हवलदार अशोक कुमार

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6126 वर्ष 2019)

जुलाई 24, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति]

सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 -विनियम 173, 173-ए -27 दिसंबर 2010 को 24 साल की सेवा का मूल कार्यकाल पूरा करने पर, अपीलकर्ता, सेना में हवलदार को 26 दिसंबर 2012 तक दो साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया था -विस्तारित कार्यकाल के दौरान, उन्हें स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और उन्हें 80% विकलांगता के साथ SHAPE-3 (स्थायी) के रूप में वर्णित श्रेणी में पुन: वर्गीकृत किया गया - अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया -अपीलकर्ता के विकलांगता पेंशन अनुदान के दावे को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा अनुमति दी गई थी -अपीलकर्ता ने 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी सर्कुलर के आधार पर 9,00,000/- रुपये के अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की मांग करते हुए एएफटी का रुख किया -अस्वीकार कर दिया - अपील पर, माना गया: गुण-दोष के आधार पर, अपीलकर्ता को 1961 के विनियमों के तहत विकलांगता पेंशन प्रदान की गई थी- विनियम 173 ऐसे व्यक्ति को विकलांगता पेंशन देने का प्रावधान करता है जो किसी गैर-युद्ध दुर्घटना में सैन्य सेवा के कारण होने वाली या बढ़ जाने वाली विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य हो जाता है, जहां विकलांगता 20% या उससे अधिक आंकी जाती है - विनियम 173-ए विकलांगता पेंशन के प्रावधान को एक काल्पनिक आधार पर विस्तारित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति जिसे विस्तारित सेवा के दौरान निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और परिणामस्वरूप सेवामुक्त कर दिया गया है, वह भी विकलांगता पेंशन के अनुदान के दायरे में आएगा -डीमिंग फिक्शन विनियम 173-ए में निर्दिष्ट सीमा तक लाभ देने तक ही सीमित है - प्रारंभ में भारत सरकार के 4 जून 2010 के नीतिगत निर्णय द्वारा, मृत्यु के मामलों में निकटतम परिजनों को अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया गया था - इसे 26 दिसंबर 2011 को उन कर्मियों के लिए बढ़ा दिया गया था जो सैन्य सेवा के कारण या बढ़े हुए कारणों से अक्षम या अक्षम हैं - अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से नीति परिपत्र की उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया क्योंकि उसे सैन्य सेवा के कारण विकलांगता/युद्ध की चोट के कारण सेवा से बाहर नहीं किया गया था - वह विनियम 173-ए के मद्देनजर विकलांगता पेंशन का हकदार था -गौरतलब है कि विनियम 173-ए के तहत, उसे विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा से अमान्य माना गया है - विनियमन 173-ए के तहत कल्पना को 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी दस्तावेज़ तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है -यदि नीति का इरादा विकलांगता पेंशन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह मुआवजा देना था, तो इसमें यह प्रावधान किया गया होता -अनुग्रह मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता था - सशस्त्र बल - सेवा कानून - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश II, नियम 2।

अपीलकर्ता सेना में हवलदार है और उसने 27 दिसंबर 2010 को 24 साल की सेवा का अपना मूल कार्यकाल पूरा किया। उन्हें 26 दिसंबर 2012 तक दो साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। विस्तारित कार्यकाल के दौरान, अपीलकर्ता को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और उसे 80% विकलांगता के साथ SHAPE-3 (स्थायी) के रूप में वर्णित श्रेणी में फिर से वर्गीकृत किया गया। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 2013 में,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता ने विकलांगता पेंशन की मांग के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की प्रधान पीठ का रुख किया। एएफटी द्वारा दावे की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, विकलांगता पेंशन को पूर्णांकित करने का दावा इस परिकल्पना पर खुला रखा गया था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था। अपीलकर्ता ने एएफटी के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दे दी गई। एएफटी ने माना कि वास्तव में, उसके इस निष्कर्ष में गलती हुई कि राउंड ऑफ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था और अपीलकर्ता 80% से 100% तक राउंड ऑफ का लाभ पाने का हकदार था। 2016 में, अपीलकर्ता ने 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी सर्कुलर के आधार पर 9,00,000/- रुपये के अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की मांग करते हुए एएफटी का रुख किया। दावे को एएफटी ने खारिज कर दिया था। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1.1 विनियम 173 सेना के लिए पेंशन विनियम 1961 ऐसे व्यक्ति को विकलांगता पेंशन देने का प्रावधान करता है जो विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गया हो या किसी गैर-युद्ध दुर्घटना में सैन्य सेवा के कारण बढ़ जाना, जहां विकलांगता का आकलन 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो। विनियम 173-ए विकलांगता पेंशन के प्रावधान को एक कल्पना द्वारा विस्तारित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति जिसे विस्तारित सेवा के दौरान निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और परिणामस्वरूप सेवामुक्त कर दिया गया है, वह भी विकलांगता पेंशन के अनुदान के दायरे में आएगा। एक व्यक्ति, जिसे निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और छुट्टी दे दी गई है, उसे भी विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा से अमान्य माना जाता है। डीमिंग फिक्शन विनियम 173-ए में निर्दिष्ट सीमा तक लाभ देने तक ही सीमित है। प्रारंभ में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नीतिगत निर्णय दिनांक 4 जून 2010 द्वारा, मृत्यु के मामलों में निकटतम परिजनों को अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया गया था। इसे 26 दिसंबर 2011 को उन कर्मियों के लिए बढ़ा दिया गया था जो सैन्य सेवा के कारण या बढ़े हुए कारणों से अक्षम या अक्षम हैं। [पैरा 9-11] [37-सी-एफ]

1.2 अनुग्रह मुआवजे के अनुदान का हकदार होने के लिए, यह आवश्यक है कि आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: (i) आवेदक को वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में अक्षम या अक्षम होना चाहिए; और (ii) आवेदक को सैन्य सेवा के कारण विकलांगता/युद्ध में लगी चोट या उसके बढ़ने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया होना चाहिए। यदि नीति का इरादा विकलांगता पेंशन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह मुआवजा देना था, तो उसने ऐसा प्रदान किया होता। 21 सितंबर 1998 को, सेना मुख्यालय ने सेवा विस्तार के लिए अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रक्रिया और मानदंड प्रदान किए। स्क्रीनिंग बोर्ड द्वारा दो साल के विस्तार के लिए सभी पीबीओआर की जांच की जानी है। पॉलिसी निर्देश के अनुबंध बी में विस्तारित कार्यकाल के दौरान प्रतिधारण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। [पैरा 12-14] [38-बी-ई]

1.3 यह इंगित करता है कि एक व्यक्ति जिसे युद्ध में हताहत या कार्रवाई में घायल व्यक्ति को छोड़कर, स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है, और परिणामस्वरूप विस्तारित सेवा के दौरान स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है, उसे मौजूदा नियमों के तहत छुट्टी दे दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसे निःसंदेह सेवामुक्त किया गया है, वह पेंशन विनियमों के विनियम 173-ए में उल्लिखित कल्पना के आधार पर विकलांगता पेंशन के लाभ का हकदार होगा। हालाँकि, यह वास्तव में व्यक्ति को अनुग्रह मुआवजे के अनुदान का हकदार

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं बनाता है। अनुग्रह मुआवजे का मामला 26 दिसंबर 2011 के नीति परिपत्र में निहित शासकीय शर्तों के दायरे में आना चाहिए। अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से पॉलिसी सर्कुलर की उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया क्योंकि उसे सैन्य सेवा के कारण विकलांगता/युद्ध की चोट या उसके बढ़ने के कारण सेवा से बाहर नहीं किया गया था। विनियम 173-ए में निहित प्रावधानों के मद्देनजर वह विकलांगता पेंशन के हकदार थे। गौरतलब है कि विनियम 173-ए के तहत, विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए उन्हें सेवा से अमान्य माना गया है। विनियमन 173-ए के तहत कल्पना को 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी दस्तावेज़ तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अनुग्रह मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता था। [पैरा 15-17] [39-बी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6126 वर्ष 2019

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2018 के विरुद्ध मूल आवेदन संख्या 1232 वर्ष 2016 में

वी.एस. तोमर, अंबरीश कुमार अग्रवाल अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

के. एम. नटराज, एएसजी, अमित वर्मा, शैलेश मडियाल, देबाशीष आर., शरथ नारायण नांबियार, सुधांशु प्रकाश, विनायक शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति डॉ. धनन्जय वाई चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया।

1. विलम्ब क्षमा किया गया।

2. अपीलकर्ता भारतीय सेना में हवलदार था। उन्होंने 27 दिसंबर 2010 को चौबीस साल की सेवा का अपना मूल कार्यकाल पूरा किया। उन्हें 26 दिसंबर 2012 तक दो साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। अपीलकर्ता को यह विस्तार सेना मुख्यालय के 21 सितंबर 1998 के नीति पत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया था जिसका शीर्षक है:

"अधिकारी रैंक (पीबीओआर) से नीचे के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रक्रिया और मानदंड"

3. अपने विस्तारित कार्यकाल के दौरान, अपीलकर्ता को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा और उसे 80% विकलांगता के साथ SHAPE- 3 (स्थायी) के रूप में वर्णित श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया गया। रिलीज़ मेडिकल बोर्ड ने पाया कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी या बढ़ी थी। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

4. विकलांगता पेंशन की मांग करते हुए, अपीलकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ में याचिका दायर की। 2 जुलाई 2014 को, एएफटी ने मूल आवेदन को यह मानते हुए अनुमति दी कि अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार था। हालाँकि, विकलांगता पेंशन को पूर्णांकित करने का दावा इस परिकल्पना पर खुला रखा गया था कि मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था।

5. अपीलकर्ता ने एएफटी के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया जिसे 30 अक्टूबर 2014 को अनुमति दे दी गई। एएफटी ने माना कि वास्तव में, यह निष्कर्ष निकालने में गलती हुई कि राउंड ऑफ का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित था। इसलिए, एएफटी ने माना कि अपीलकर्ता 80% से 100% तक पूर्णांकन के लाभ का हकदार था।

6. अपीलकर्ता ने 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी सर्कुलर के आधार पर 9,00,000 रुपये के अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की मांग करते हुए 2016 में एएफटी का रुख किया। एएफटी ने निम्नलिखित आधार पर दावे को खारिज कर दिया:

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(i) ऐसा दावा कार्यवाही के पहले दौर में एएफटी के समक्ष किया जाना चाहिए था और मूल आवेदन या समीक्षा में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, ऐसी राहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश II नियम 2 द्वारा वर्जित थी। ;

(ii) चूंकि अपीलकर्ता को 2012 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए दावा सीमित कर दिया गया था और 2016 में ही ऐसी राहत के लिए एएफटी को स्थानांतरित किया गया था; और

(iii) योग्यता के आधार पर, अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए आवश्यक आवश्यकता यह थी कि आवेदक को विकलांगता के आधार पर सेवा से अमान्य कर दिया गया हो। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को, चौबीस साल की सेवा पूरी करने पर, दो साल का विस्तार दिया गया था और विस्तारित अवधि के दौरान उसे निम्न चिकित्सा श्रेणी में पदावनत किए जाने पर छुट्टी दे दी गई थी।

7. एएफटी ने सेना के लिए पेंशन विनियमों के नियम 2 से जुड़े नोट पर भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विकलांगता पेंशन के उद्देश्य के लिए। विस्तारित कार्यकाल के दौरान सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति को केवल विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए अमान्य माना जाता है। एएफटी के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है। 'मूल आवेदन क्रमांक 321 वर्ष 2013।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वीएस तोमर ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ बनाम राम अवतार मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकाला कि क्या कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है या नियुक्ति के कार्यकाल के पूरा होने पर सैन्य सेवा के कारण होने वाली या बढ़ने वाली विकलांगता से पीड़ित पाए जाने पर विकलांगता पेंशन को पूर्णांकित करने के लाभ का हकदार है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने तर्क दिया कि राउंड ऑफ का यह लाभ केवल सशस्त्र बल के उन कर्मियों को उपलब्ध है जो सेवा से बाहर हो गए हैं, किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं। एएफटी के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए इस दलील को खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले में, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, अपीलकर्ता, जो सेवा के विस्तारित कार्यकाल पर था, को समय से पहले बंद कर दिया गया था और इसे सेवा से अमान्य माना जाना चाहिए। इस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता 26 दिसंबर 2011 के नीति परिपत्र के अनुसार अनुग्रह मुआवजे का हकदार होगा।

9. अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई दलीलों का विरोध करते हुए श्री केएम नटराज ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि संक्षेप में, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे विकलांगता पेंशन दी गई है, उसे आवश्यक रूप से अनुग्रह भुगतान मिलना चाहिए। यह आग्रह किया गया था कि यह न तो नीति परिपत्र का इरादा है और न ही उद्देश्य है। प्रस्तुतीकरण के अनुसार, 4 जून 2010 की मूल नीति में निर्धारित सेवा के दौरान कर्तव्यों के दौरान मरने वाले सेना कर्मियों को अनुग्रह मुआवजे का अनुदान बाद में 26 दिसंबर 2011 को बढ़ा दिया गया था। 26 दिसंबर 2011 की नीति की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि यह उन रक्षा सेवा कर्मियों पर लागू होती है जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में अक्षम या अक्षम हैं और सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई विकलांगता/युद्ध चोट के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए हैं। आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता के मामले में यह शर्त पूरी नहीं होती है। अपीलकर्ता से आग्रह किया गया था कि उसे 21 सितंबर 1998 के सेना मुख्यालय

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नीति निर्देश के अनुसार दो साल की सेवा का विस्तारित कार्यकाल दिया गया था, जिसके तहत विस्तारित कार्यकाल के दौरान प्रतिधारण कुछ शर्तों के अधीन है। उन शर्तों में से एक यह है कि जिस व्यक्ति को स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है (उन लोगों को छोड़कर जो युद्ध में हताहत हुए हैं या कार्रवाई में घायल हुए हैं), उन्हें 10 दिसंबर 2014 को तय किए गए मौजूदा नियम 4 सिविल अपील संख्या 418 वर्ष 2012 के तहत छुट्टी दे दी जाएगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलकर्ता को उन शर्तों के अनुसार सेवामुक्त कर दिया गया था जिसके अधीन उसे विस्तारित कार्यकाल दिया गया था, वह अनुग्रह मुआवजे के लाभ का हकदार नहीं होगा। यह आग्रह किया गया है कि यदि नीति परिपत्र में यह दर्शाया गया होता कि प्रत्येक व्यक्ति जो विकलांगता पेंशन का हकदार है, वह भी अनुग्रह राशि का हकदार होगा, तो उस आशय का एक विशिष्ट प्रावधान किया गया होता।

10. हालांकि एएफटी ने अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अनुग्रह मुआवजे का दावा पहले दौर में नहीं किया गया था और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 2 और सीमा दोनों द्वारा वर्जित है, हम इस अपील में मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर तय करने का प्रस्ताव करते हैं। इसलिए, हम इन तकनीकीताओं में नहीं गए हैं। हमने दावे की खूबियों पर ध्यान दिया क्योंकि पूरी निष्पक्षता से यही वह आधार है जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दावे का विरोध किया गया है।

11. सबसे पहले, उन परिस्थितियों की सराहना करना आवश्यक होगा जिनमें अपीलकर्ता को सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 के तहत विकलांगता पेंशन दी गई थी। विनियम 173 और 173-ए इस मामले पर असर डालते हैं। वे इस प्रकार प्रदान करते हैं:

"विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए प्राथमिक शर्तें 173 जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, सेवा तत्व और विकलांगता तत्व से युक्त विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है, जो किसी विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गया है, जिसके लिए जिम्मेदार है या गैर-युद्ध हताहत में सैन्य सेवा से बढ़ गया है और इसका मूल्यांकन 20 प्रतिशत या उससे अधिक है। यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण है या बढ़ गई है, परिशिष्ट आईएल में नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। व्यक्तियों को स्थायी रूप से निम्न चिकित्सा श्रेणी में रहने के कारण छुट्टी दे दी गई।

173-ए. ऐसे व्यक्ति जिन्हें निम्न चिकित्सा श्रेणी ('ई' के अलावा) में स्थायी रूप से रखा गया है और जिन्हें छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उनके अपने व्यापार/श्रेणी में उनकी निम्न चिकित्सा श्रेणी के लिए उपयुक्त कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका है या जो वैकल्पिक रोजगार स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं या जिन्हें वैकल्पिक नियुक्ति में बनाए रखा गया है, उन्हें उनकी नियुक्ति पूरी होने से पहले सेवामुक्त कर दिया गया है, उन्हें इन विनियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा से अमान्य माना जाएगा।

टिप्पणी। उपरोक्त प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिन्हें विस्तारित सेवा के दौरान निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और उनके विस्तार की अवधि पूरी होने से पहले उस कारण से छुट्टी दे दी गई है।

12. विनियम 173 ऐसे व्यक्ति को विकलांगता पेंशन देने का प्रावधान करता है, जो किसी गैर-युद्ध दुर्घटना में सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गया है, जहां विकलांगता का आकलन 20 प्रतिशत या उससे अधिक है। विनियम 173-ए विकलांगता पेंशन के प्रावधान को एक कल्पना द्वारा विस्तारित करता है जिसके तहत एक

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

व्यक्ति जिसे विस्तारित सेवा के दौरान निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और परिणामस्वरूप सेवामुक्त कर दिया गया है, वह भी विकलांगता पेंशन के अनुदान के दायरे में आएगा। एक व्यक्ति, जिसे निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और छुट्टी दे दी गई है, उसे भी विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा से अमान्य माना जाता है। डीमिंग फिक्शन विनियम 173-ए में निर्दिष्ट सीमा तक लाभ देने तक ही सीमित है।

13. यह हमें मूल मुद्दे को निर्धारित करने की ओर ले जाता है कि क्या अपीलकर्ता ने अनुग्रह मुआवजे के अनुदान की आवश्यकता को पूरा किया है। प्रारंभ में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के 4 जून 2010 के एक नीतिगत निर्णय द्वारा मृत्यु के मामलों में निकटतम परिजनों को अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया गया था। इसे 26 दिसंबर 2011 को उन कर्मियों के लिए बढ़ा दिया गया था जो सैन्य सेवा के कारण या बढ़े हुए कारणों से अक्षम या अक्षम हैं। हालाँकि, 26 दिसंबर 2011 के पॉलिसी परिपत्र के पैरा 3 में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

“3. राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे रक्षा सेवा कर्मी, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में अक्षम हैं, अक्षम हैं और सैन्य सेवा के कारण या वृद्धि के कारण विकलांगता/युद्ध की चोट के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए हैं, 100% विकलांगता के लिए 9 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। 100% से कम लेकिन 20% से कम नहीं विकलांगता/युद्ध चोट के लिए, अनुग्रह मुआवजे की राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। 20% से कम विकलांगता/युद्ध चोट के लिए कोई अनुग्रह मुआवजा देय नहीं होगा। आनुपातिक मुआवज़ा इस मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र दिनांक 31.01.2001 के पैरा 7.2 में निहित बोर्ड बैंडिंग प्रावधानों को लागू किए बिना अमान्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित विकलांगता के वास्तविक प्रतिशत पर आधारित होगा।

14. अनुग्रह मुआवजे के अनुदान का हकदार होने के लिए, यह आवश्यक है कि आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

@) आवेदक को वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम या अक्षम होना चाहिए; और

(ii) आवेदक को सैन्य सेवा के कारण विकलांगता/युद्ध में लगी चोट या उसके बढ़ने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया होना चाहिए।

15. यदि नीति का इरादा विकलांगता पेंशन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह मुआवजा देना था, तो उसने ऐसा प्रदान किया होता।

16. 21 सितंबर 1998 को सेना मुख्यालय ने सेवा विस्तार के लिए अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रक्रिया और मानदंड प्रदान किए। स्क्रीनिंग बोर्ड द्वारा दो साल के विस्तार के लिए सभी पीबीओआर की जांच की जानी है। पत्र के पैरा 5 में प्रावधान है:

“5. विस्तारित कार्यकाल के दौरान पीबीओआर को बनाए रखना। विस्तारित कार्यकाल के दौरान पीबीओआर का प्रतिधारण इस पत्र के अनुबंध 'बी' के अनुसार विचारों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा”।

17. पॉलिसी निर्देश के अनुबंध बी में विस्तारित कार्यकाल के दौरान प्रतिधारण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"1. विस्तारित कार्यकाल के दौरान पीबीओआर का प्रतिधारण निम्नलिखित विचार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा: -जी) चिकित्सा मानक व्यक्ति को चिकित्सा श्रेणी 'एवाईई' पीबीओआर में बने रहना चाहिए, जो स्क्रीनिंग बोर्ड के समय और साथ ही सेवा के विस्तार की अवधि के दौरान अस्थायी रूप से निम्न चिकित्सा श्रेणी में हैं, वे सेवा में बने रहेंगे। यदि इस अस्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी को स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में बनाया जाता है तो इसे स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में बनाया जाता है, सिवाय युद्ध में घायल हुए लोगों को छोड़कर और परिणामस्वरूप एलएमसी (पीटी) 5 में रखा गया "बढ़ी हुई सेवा के दौरान अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्तियों को मौजूदा नियमों के तहत सेवामुक्त कर दिया जाएगा।"

18. यह इंगित करता है कि एक व्यक्ति जिसे युद्ध में हताहत या कार्रवाई में घायल व्यक्ति को छोड़कर स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है, और परिणामस्वरूप विस्तारित सेवा के दौरान स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है, उसे मौजूदा नियमों के तहत छुट्टी दे दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसे निःसंदेह सेवामुक्त किया गया है, वह पेंशन विनियमों के विनियम 173-ए में उल्लिखित कल्पना के आधार पर विकलांगता पेंशन के लाभ का हकदार होगा। हालाँकि, यह वास्तव में व्यक्ति को अनुग्रह मुआवजे के अनुदान का हकदार नहीं बनाता है। अनुग्रह मुआवजे का मामला 26 दिसंबर 2011 के नीति परिपत्र में निहित शासकीय शर्तों के दायरे में आना चाहिए।

19. अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से पॉलिसी परिपत्र की उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया क्योंकि उसे सैन्य सेवा के कारण विकलांगता/युद्ध की चोट के कारण या बढ़ जाने के कारण सेवा से बाहर नहीं किया गया था। विनियम 173-ए में निहित प्रावधानों के मद्देनजर वह विकलांगता पेंशन के हकदार थे। गौरतलब है कि विनियम 173-ए के तहत, विनियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित पात्रता नियमों के प्रयोजन के लिए उन्हें सेवा से अमान्य माना गया है। विनियमन 173-ए के तहत काल्पनिकता को 26 दिसंबर 2011 के नीति दस्तावेज़ तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

20. नतीजतन, हमारा मानना है कि जिन कारणों से हमने संकेत दिया है, उनके आधार पर अनुग्रह मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

21. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

22. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे अपील खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"